

जीएसपी मूलस्थान प्रमाण पत्र - निर्यातकों के लिए एक मार्गदर्शन

1.0 प्रस्तावना

वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) विकसित देशों (वरीयता देने वाले या दाता देशों के रूप में ज्ञात देशों) द्वारा विकासशील देशों के लिए (वरीयता प्राप्त करने देशों या लाभार्थी देशों के रूप में ज्ञात) विस्तारित एक अधिमान्य टैरिफ प्रणाली है। इसमें दाता देशों के बाजारों को लाभार्थी देशों द्वारा निर्यातित योग्य उत्पादों के लिए कम किया हुआ एमएफएन प्रशुल्क या शुल्क मुक्त प्रवेश शामिल है।

2.0 जीएसपी के लाभ

2.1 भारतीय निर्यातकों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ : - यह लाभ योग्य भारतीय उत्पादों के लिए कम किए हुए टैरिफ या कर मुक्त प्रवेश के माध्यम से आयातक के लिए देय लाभ के रूप में है।

2.2 एक भारतीय उत्पाद पर आयात शुल्क कम किया जाना या हटाया जाना आयातक के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है- अन्य बातें (उदाहरण के लिए गुणवत्ता) समान हैं।

2.3 यह टैरिफ अधिमान्य दाता देश में नए निर्यातकों को एक बाजार में प्रवेश करने के लिए और प्रतिष्ठित निर्यातकों को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए और लाभ प्रतिशत पर सुधार करने के लिए, मदद करता है।

3.0 देश जहां जीएसपी लाभ लागू है

3.1 वर्तमान समय में जीएसपी 29 विकसित देशों द्वारा विस्तारित है

ऑस्ट्रेलिया	बुल्गारिया गणराज्य	* यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य	
कनाडा	हंगरी गणराज्य	ऑस्ट्रिया	इटली
चेक गणतंत्र	पोलैंड गणराज्य	बेल्जियम	लक्जमबर्ग
यूरोपीय संघ*	रूसी संघ	डेनमार्क	नीदरलैंड्स
जापान	स्लोवाकिया	फिनलैंड	पुर्तगाल
न्यूजीलैंड	स्विट्जरलैंड	फ्रांस	स्पेन
बेलारूस के नॉर्वे गणराज्य	संयुक्त राज्य अमरीका	जर्मनी	स्वीडन
		यूनान	यूनाइटेड किंगडम
		आयरलैंड	

3.2 इसके अलावा, यह समझा जाता है कि कजाखस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया और यूक्रेन भी अधिमान्य टैरिफ चयनित भारतीय वस्तुओं के लिए अनुमति दी जाती है।

4.0 योग्य उत्पाद

4.1 एक लाभार्थी देश (भारत जैसा) आयात करने वाले देश द्वारा निर्धारित मूल के नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, के केवल उन्हीं उत्पादों को बिंदु 3 के तहत विस्तृत दाता देशों के बाजारों में आयात पर अधिमान्य टैरिफ के योग्य माना जाता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के 15 सदस्य देशों के मामले में एक भारतीय उत्पाद को केवल तभी योग्य माना जाता है जब यह मूल के समुदाय कानून अर्थात् विनियमन (ईईसी) नं 2454/93 , (ईसी) सं. 12/97 और विनियमन (ईसी) सं.: 1602/2000 जैसा विनियमन द्वारा संशोधित निर्धारित नियमों, की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

5.0 मूल के नियम

5.1 मूल के नियमों में देश में आयात पर अधिमान्य टैरिफ के लिए पात्र होने के लिए आयात करने वाले देश द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं की एक श्रेणी, जो एक उत्पाद के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए शामिल है।

5.2 मूल के नियम का उद्देश्य, जहां तक संभव हो, यह अधिमान्य प्रणाली के लाभ जिस देश के लिए इच्छित हो, और अनावश्यक रूप से प्रणाली के शोषण करने से तीसरे देशों के माल को रोकने के आरक्षित करने के लिए कर रहे हैं। इसका राष्ट्रीय कोटा और

निर्धारण पुनः शुरू होने के मामले में विशेष महत्व हो सकता है। दूसरी ओर, उद्योगों की आवश्यकता कच्चे माल के स्रोत, और अर्द्ध निर्मित अन्य देशों से उत्पादों या भागों को, कई मामलों में, किसी तीसरे देश की सामग्री के रूप में स्वीकार करते हुए, ध्यान में रखा जाता है।

5.3 मूल के नियमों के तीन घटक हैं:

- (क) उत्पत्ति मानदंड - जो एक उत्पाद लाभार्थी देश में उत्पन्न हुआ हो, या जिस देश से उत्पाद निर्यात किया जा रहा, को निर्धारित किया जाता है (मद 6 देखें)
- (ख) परिवहन शर्तें : जो निर्यात के देश से परेषिती के देश के लिए परिवहन के साधन को निर्दिष्ट करता है, ताकि जो निर्यात के देश से परेषिती के देश में आयात पर उत्पाद अधिमान्य टैरिफ के लिए योग्यता प्राप्त करता है (मद 11 देखें)
- (ग) दस्तावेजी प्रमाण - यह दाता देश की सीमा पर, (बिंदु 12 देखें) जीएसपी लाभ प्रदान किए जाने वाले उत्पाद के लिए प्रमाण के तौर पर काम आएगा।

Documentary Evidence - that will serve as the proof for goods to be granted GSP benefits at the border of the donor country, (see point 12)

5.4 उपरोक्त के अलावा, कुछ पूरक नियम उत्पाद जो, मूल पर प्रभावित हो सकता है, विचाराधीन है (मद 10 देखें)।

6.0 जीएसपी के लाभ

6.1 भारत से निर्यातित उत्पादों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता - पूरी तरह से प्राप्त उत्पाद और आयात सामग्री के साथ उत्पाद

6.2 पूरी तरह से प्राप्त उत्पाद वह है, जो पूरी तरह से किया गया है,

- (क) उगाया
- (ख) मिट्टी से निकाले
- (ग) देश के भीतर का पैदावार या
- (घ) ऊपर से विशेष रूप से निर्मित

6.3 **पूरी तरह से प्राप्त उत्पाद** किसी भी सामग्री के पूर्ण अभाव के आधार पर या उनके निर्माण में आयातित / अज्ञात मूल के घटकों के आधार पर जीएसपी लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करना।

6.4 **आयात सामग्री के साथ उत्पाद जो** सामग्री, भागों या घटक भारत में या अज्ञात मूल के आयात से पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्माण किया जाता है।

6.5 **आयात सामग्री के साथ उत्पाद**, यदि निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, भागों या घटकों भारत में आयातित या अज्ञात मूल की हो, पर्याप्त कार्यशील या प्रसंस्करण के अधीन हो तो जीएसपी के लिए योग्य है (मद 8 देखें)। दूसरी ओर, एक उत्पाद यदि आयातित सामग्री केवल भारत में न्यूनतम संचालन के अधीन हो, गैर उत्पत्ति के आयातित उत्पाद के उपयोग के साथ हो, (मद 9 देखें)

6.6 हालांकि वे आयात की गई हो अज्ञात मूल की सामग्री मानी जाएगी

6.7 लाभार्थी देश में किसी रूकावट के बिना उद्गम स्थिति के अधिग्रहण के लिए निर्धारित मानदंड को संतुष्ट किया जाना चाहिए।

7.0 पूरी तरह से प्राप्त उत्पाद

7.1 आयातित या अज्ञात मूल की सामग्री के उपयोग के बिना प्राप्त किसी भी उत्पाद को पूरी तरह से प्राप्त उत्पाद कहा जाता है।

7.2 **पूरी तरह से प्राप्त** मानदण्डों की सख्ती से व्याख्या की जाती है। यहाँ तक कि "सामग्री, भागों या आयातित या अज्ञात मूल के घटक" की एक न्यूनतम सामग्री तैयार उत्पाद को पूरी तरह से प्राप्त अपनी योग्यता को खो देता है।

- 7.3 उत्पाद के निम्न श्रेणियों को पूर्णतः भारत में प्राप्त माना जाता है,
- (क) खनिज उत्पादों अपनी धरती से या उसके समुद्र-बिस्तर से निकाले गए: या, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, हंगरी, रूस और स्लोवाकिया के मामले में भारतीय क्षेत्र में या उसके महाद्वीपीय शैल से निकाले गए खनिज उत्पादों;
- (ख) भारत में उगाई सब्जी उत्पाद
- (ग) भारत में पैदा होकर बड़े हुए जानवर
- (घ) जीवित पशुओं से भारत में प्राप्त उत्पाद;
- (ङ.) भारत में अहेर या मत्स्य ग्रहण से प्राप्त उत्पाद;
- (च) समुद्र में मत्स्य ग्रहण से प्राप्त उत्पाद और उसके जहाजों द्वारा समुद्र से प्राप्त अन्य उत्पाद; और यह भी, भारत द्वारा चार्टर्ड जहाजों द्वारा; बुल्गारिया के पूर्व में, चेक गणराज्य, हंगरी, रूस और स्लोवाकिया से प्राप्त उत्पाद,
- (छ) (ऊपर 0 में संदर्भित उत्पादों के रूप में अपनी फैक्ट्री जहाजों विशेष रूप से बोर्ड पर बने उत्पाद, और भी बुल्गारिया, चेक गणराज्य, हंगरी, रूस और स्लोवाकिया के मामले में, भारत द्वारा चार्टर्ड फैक्ट्री जहाजों ।
- (ज) केवल कच्चे माल की पुनर्प्राप्ति हेतु भारत में एकत्र प्रयुक्त सामान ;
- (झ) भारत में किए गए निर्माण कार्यों से उत्पन्न बेकार और स्क्रेप,; तथा ;
- (ञ) भारत में प्राप्त उत्पाद विशेष रूप से ऊपर (क) से (i) तक निर्दिष्ट 'उत्पाद (जैसे लोहे की शीट और लौह अयस्क से उत्पादित बार, सूती कपड़े, कच्चे कपास से बुना; इस्तेमाल किए हुए मोटर कार बैटरी से निकाले लेड , धातु छीलन, से धातु की प्राप्ति आदि) ।
- ऊपर (च) और (छ) में इस्तेमाल, शब्द "जहाज" या "फैक्ट्री जहाज ", यूरोपीय संघ, नार्वे, पोर्लैंड और स्विट्जरलैंड द्वारा विस्तार में परिभाषित किया गया है
- 7.4 न्यूजीलैंड, आयातित कच्चे माल से पूरी तरह से भारत में उत्पादित सामान को उनके स्रोत के बावजूद, जैसा प्राप्त है स्वीकार करता है ।
- 8.0 पर्याप्त कार्यशील या प्रसंस्करण**
- 8.1 पर्याप्त काम या प्रसंस्करण की आवश्यकता केवल तब पैदा होती है जब एक उत्पाद पूरी तरह या आंशिक, सामग्री, या तो भागों या आयातित या अज्ञात मूल की घटकों से निर्मित हो ।
- 8.2 दाता देश पर्याप्त कार्यशील या प्रसंस्करण को प्राप्त करने के लिए दो मुख्य मापदंड का पालन करते हैं । ये प्रक्रिया मानदंड और प्रतिशत मानदंड हैं।
- 8.3 प्रक्रिया मानदंड 19 देशों द्वारा पालन किया जाता है - यूरोपीय संघ के 15 सदस्य राज्यों, जापान, नार्वे, पोर्लैंड और स्विट्जरलैंड। सामान्य रूप से , जब आयात देश से एक सूची में निर्धारित उत्पाद के शर्तों को पूरा किया जाता है तब पर्याप्त काम या प्रसंस्करण हो जाता है।
- 8.4 सूची में निर्धारित शर्तें आवश्यक काम या प्रसंस्करण की न्यूनतम मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं और अधिक काम या प्रसंस्करण भी उद्गम स्थिति प्रदान करता है ; इसके विपरीत, कम काम या प्रसंस्करण से उद्गम का दर्जा प्रदान नहीं कर सकते ।
- 8.5 ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बुल्गारिया, कनाडा, चेक गणराज्य, हंगरी, न्यूजीलैंड, रूस, स्लोवाकिया और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) - प्रतिशत मानदंड शेष 10 देशों द्वारा लागू किया जाता है। प्रतिशत मानदंड आयातित सामग्री, भागों या घटकों के अधिकतम मूल्य (प्रतिशत के संदर्भ में) के मामले में बेलारूस, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, हंगरी, रूस और स्लोवाकिया के द्वारा लागू किया जाता है। / टिन निर्धारित किया जाता मूल, घरेलू सामग्री के निर्यात उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल किया (प्रतिशत के संदर्भ में), जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका के न्यूनतम मूल्य के संदर्भ में इसे लागू करते हैं ।
- 8.6 यह उल्लेखनीय है कि केवल उन सामग्री, उपकरणों का आयात / अज्ञात मूल के हैं जिसके भाग भारत में

उद्धव के रूप में माना जाता है तैयार उत्पाद के लिए पर्याप्त काम या प्रसंस्करण के लिए किए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, सामग्री, भागों और घटक जो पूरी तरह से भारत में प्राप्त हैं, के लिए पर्याप्त रूप से काम किया या प्रसंस्कृत नहीं किया, तैयार उत्पाद के लिए भारतीय मूल का \ माना जाता है।

9.0 न्यूनतम प्रचालन

- 9.1 एक उत्पाद "पूरी तरह से प्राप्त" नहीं है, तो (7 बिंदु देखें) और आयातित माल का उपयोग कर उत्पादन किया जाता है, की जांच करने के लिए पहली बात अगर आयातित सामग्री केवल नीचे सूचीबद्ध तथाकथित कम या अपर्याप्त में से एक प्रचालन के अधीन है।
- (क) संचालन परिवहन और भंडारण के दौरान अच्छी हालत में (वेंटिलेशन, बाहर के प्रसार; सुखाने, द्रुतशीतन, नमक, सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य जलीय घोलों में रखकर; क्षतिग्रस्त हिस्सों को हटाने, और परिचालित उत्पादों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए है।
- (ख) सरल प्रचालन में धूल निकालने, शिफ्टिंग या स्क्रीनिंग, छँटाई, वर्गीकृत करने, धुलाई, पेंटिंग, कटाई (सामग्री के सेट बनाने सहित) मैचिंग शामिल है।
- (ग) (i) पैकिंग के परिवर्तन तथा पैकेजों को निकालना एवं संयोजन
(ii) बोटलों, फ्लास्क, बैग, केसेस, बक्से में रखने, कार्ड या बोर्ड आदि पर फिक्सिंग, और अन्य सभी साधारण पैकिंग प्रचालन;
- (घ) निशान, लेबल या उत्पादों या उनकी पैकेजिंग पर अन्य ऐसे विशिष्ट संकेत की फिक्सिंग
- (ङ) उत्पादों का सरल मिश्रण, चाहे विभिन्न प्रकार के हो या नहीं, जहां मिश्रण में से एक या अधिक घटक नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते, उत्पादों की मूल उत्पत्ति के रूप मानने के लिए उन्हें सक्षम बना देते हैं ;
- (च) एक पूर्ण उत्पाद के गठन के लिए उत्पादों के कुछ हिस्सों का साधारण संयोजन
- (छ) (क) से (च) तक निर्दिष्ट दो या दो से अधिक प्रचालनों का एक संयोजन
- (ज) पशुओं के वध, जापान को छोड़कर, जो पर्याप्त प्रक्रिया के रूप में पशुओं के वध मानता है।
- 9.2 तो ऊपर (मद 9.1) के मामले में, उत्पाद मूल का नहीं हो, क्योंकि यह काफी हद तक किसी तीसरे देश में प्राप्त किया गया है।
- 9.3 हालांकि, ध्यान दिया जाना है कि ऊपर 9.1 पर उल्लिखित साधारण किस्म के परे जाना है, मिश्रण के जटिल प्रचालन, सम्मिश्रण या संयोजन मूल प्रदान कर सकते हैं।
- 9.4 सरल और जटिल प्रचालनों के बीच का अंतर विशेष कौशल, उपकरण, नियंत्रण और आवश्यक परिशुद्धता के आधार पर सामान्य रूप में निर्धारित किए जाएं या अन्यथा पूरा कर लिया जाए। उदाहरण के लिए, एक नमकीन घोल प्राप्त करने के लिए नमक और पानी के मिश्रण, एक सरल प्रक्रिया है, जबकि, नियंत्रित तापमान, दबाव और बाँझ परिस्थितियों तथा औषधीय तौर पर सक्रिय तत्वों के तहत मिश्रण काफी जटिल प्रक्रिया हो सकती है।

10.0 पूरक नियम

- 10.1 निम्नलिखित अनुपूरक नियमों के महत्व जैसा कि वे अंतिम उत्पाद के मूल पर असर पड़ सकता है, अर्थात्:
- (i) दाता देश सामग्री नियम,
- (ii) संचयन,
- (iii) "दो कदम" नियम,
- (iv) लौटी सामग्री,
- (v) तटस्थ तत्वों और

(vi) विचारार्थ यूनिट।

10.2 दाता देश सामग्री नियम के तहत,

दाता देश में उद्भूत कच्चे माल, भागों और घटकों और निर्यात वस्तुओं के निर्माण में उसी दाता देश में उद्भूत सामग्री का उपयोग करता है हालांकि एक लाभार्थी देश में उत्पन्न (भारत कहा जाए) हो, उपलब्ध कराए गए इस तरह के कच्चे माल, भागों और घटकों कार्यविधि या प्रसंस्करण के अधीन हैं, वर्णित न्यूनतम कार्यों से परे जा रहा है (मद 9 देखें)। मूल के निर्धारण करने के लिए इस तरह के उत्पादों के मूल्य में घरेलू सामग्री पर जोड़ा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, न्यूजीलैंड, नार्वे, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, -। बेलारूस, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, हंगरी, रूस और स्लोवाकिया में यह नियम लागू होता है। यूरोपीय संघ, जापान, नार्वे, पोलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ दाता देशों को उन से आयातित उत्पाद की उत्पत्ति स्थिति के दस्तावेजी प्रमाण अपेक्षित है।

10.3 संचयन उत्पत्ति स्थिति को प्रभावित किए बिना लाभार्थी देशों से श्रम, सामग्री, भागों और अन्य घटकों के साथ एक उत्पाद के निर्माण करने और एक लाभार्थी देश (भारत कहा जाए) में तैयार करने की अनुमति देता है।

(क) वैश्विक संचयन के तहत, मूल का निर्धारण करने के लिए सभी लाभार्थी देशों को एक के रूप में; एकल क्षेत्र माना जाता है। दूसरे शब्दों में, देश (भारत कहा जाए) जहां अंतिम तैयारी या प्रसंस्करण किया गया हो, से निर्यात किए जा रहे उत्पादों के लिए मूल की आवश्यकता पूरा करने के क्रम में विभिन्न लाभार्थी देशों में मूल्य वर्धित तथा/ या निष्पादित विनिर्माण-प्रक्रिया, एक साथ जोड़ी जाती है। मूल का निर्धारण करने के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों / अन्य लाभार्थी देशों में निष्पादित विनिर्माण प्रक्रिया घरेलू सामग्री पर जोड़ा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, पोलैंड, बेलारूस, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, हंगरी, रूस और स्लोवाकिया वैश्विक संचयन की अनुमति देते हैं।

(ख) क्षेत्रीय संचयन के तहत, किसी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय समूह के सदस्य देशों के मूल का निर्धारण करने के लिए एक के रूप में माना जाता है। तदनुसार, मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय समूह के सदस्य देशों में से किसी में उत्पन्न उत्पाद हो, अगर एक ही क्षेत्रीय समूह के अन्य सदस्य देशों में आगे निर्माण में उपयोग किया है, आगे के निर्माण के देश में मूल स्थान के रूप में माना जाता है। दूसरे शब्दों में, भले ही एक ही क्षेत्रीय समूह के अन्य सदस्य देशों में मूल्य वर्धन, और / या विनिर्माण प्रक्रिया निष्पादित हो, अंत में उत्पाद एक लाभार्थी सदस्य देश से निर्यात किया गया हो (भारत कहा जाए) इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। यूरोपीय संघ, जापान, नार्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में यह नियम लागू होता है। योग्य क्षेत्रीय समूहों के कुछ उदाहरण हैं:

(i) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) में ब्रुनेई - दारेस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं;

(ii) मध्य अमेरिकी साझा बाजार (सी ए सी एम) में कोस्टा रिका, होंडुरास, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पनामा और अल साल्वाडोर शामिल है ;

(iii) एंडियन समुदाय (एंडियन समूह) में बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला शामिल है ;

(iv) एक साझा बाजार कैरीबी (कैरीकॉम) में एंटीगुआ और बारबुडा, बारबाडोस, बेलिज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, जमैका, मोंटसेराट, सेंट क्रिस्टोफर-नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, और त्रिनिदाद और टोबैगो शामिल हैं ;

(v) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (एस ए ए आर सी (सार्क)) में बांग्लादेश, भूटान, भारत,

मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।

भारत, सार्क क्षेत्रीय समूह के एक सदस्य के रूप में, यूरोपीय संघ, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड की योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय संचयन सहयोग के लिए पात्र है।

एक नामित प्राधिकारी द्वारा जीएसपी फार्म ए जारी किया जाता है, तथापि, सार्क क्षेत्रीय समूह के सदस्य देश आयातित 'सामग्री की उत्पत्ति स्थिति के दस्तावेजी प्रमाण की अपेक्षा रखते हैं।

10.4 "दो कदम" नियम

जब एक आयातित सामग्री 'क', भारत में 'ख' के मूल नियम के अनुसार अन्य उत्पाद 'ख' में रूपांतरित हो जाता है, और फिर 'ख' अभी भी एक अन्य उत्पाद के रूप में सन्निहित है, पूरे उत्पाद 'ख' को उत्पत्ति स्थान माना जाता है, जब 'ग' के मूल निर्धारित किया जाना है।

10.5 लौटाए उत्पाद

भारत से एक देश के लिए निर्यात किए गए मूल उत्पाद भारत वापस लौटा जाता है तो, उसे आयातित के रूप में (या गैर मूल के उत्पाद) माना जाता है जब तक कि यह संतोषजनक ढंग से स्थापित किया जा सकता है कि

- लौटाए उत्पाद वही है, जो निर्यात किया गया था तथा;

- लौटाए गए उत्पाद उस देश में अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया के परे किसी भी प्रक्रिया के अधीन नहीं रहे हैं।

10.6 तटस्थ तत्व

एक उत्पाद के अंतिम संयोजन में, उत्पाद प्रवेश नहीं करते, और प्रवेश करने का इरादा नहीं है, जो कि उत्पाद के मूल को प्रभावित नहीं करते। दूसरे शब्दों में, उत्पाद के मूल का निर्धारण करने पर एक उत्पाद प्राप्त करने के लिए उपयोग किए ऊर्जा, ईंधन, संयंत्र, उपकरण, मशीन या उपकरण के मूल को ध्यान में नहीं रखा जाता है ;

10.7 विचार की इकाई

(क) उत्पाद के मूल का निर्धारण के प्रयोजन के लिए, एक परेषण में प्रत्येक सामग्री का अलग से विचार किया जाना है इसके सिवाय कि -

(i) जहां एक समूह, सेट या उत्पाद के संयोजन एक टैरिफ मद या कोड में वर्गीकृत किया जाता है, उस समूह, सेट या संयोजन को एक उत्पाद माना जाता है, और

(ii) यह सामग्री के साथ आयातित उपकरण, भागों और उपसाधन -मानक उपकरण के गठन करता है, साधारणतः उस तरह के उपकरण की कीमत बिक्री में शामिल है, और जिसके लिए अलग से कोई प्रभार नहीं है उत्पाद के साथ एक पूरे गठन के रूप में माना जाता है।

(ख) एक गैर संयोजित उत्पाद जो कि एक से अधिक लदान में भेजा जाता है क्योंकि यह आयातक के परिवहन उत्पादन कारणों से व्यवहार्य नहीं है, एक उत्पाद के रूप में माना जाता है।

(ग) अनुरूपता प्रणाली के सामान्य नियम 3 में परिभाषित उत्पाद सेट जब घटक सामग्री मूल उत्पाद हो मूल के रूप में माना जाता है। यदि एक सेट मूल और गैर मूल के उत्पाद से बने हो, तो उस पूरे सेट को मूल के रूप में माना जाएगा जब कि गैर मूल के वस्तुओं का मूल्य सेट के पूर्व काम के 15% से अधिक न हो।

धारा 4

दवा उत्पादन तथा लेन देन से निपटने के लिये विशेष व्यवस्थाएं

अनुच्छेद 10

अनुबंध IV के अनुसार उत्पादों पर जो, सामान्य सीमा शुल्क टैरिफ मूल्यानुसार कर में शीर्षक IV में संदर्भित दवा

उत्पादन तथा लेन देन से निपटने की विशेष व्यवस्थाओं में शामिल किए गए हैं और अनुलग्नक 1 के कॉलम 1 के अनुसार जो एक देश में उत्पन्न हो इस व्यवस्था से लाभ मिल सकें पूरी तरह से निलंबित किया जाएगा। सीएन कोड 0306 13 के उत्पादों के लिए, कर 3.6% की दर पर कम कर दिया जाएगा।

जिन उत्पादों के लिए आम सीमा शुल्क टैरिफ तथा मूल्यानुसार कर शामिल हैं, उन्हें छोड़कर पैरा 1 में निर्दिष्ट उत्पादों पर सीमा शुल्क टैरिफ आम विशिष्ट कर को पूरी तरह निलंबित किया जाएगा। सीएन कोड 1704 10 91 और 1704 10 99 के उत्पादों के लिए, विशिष्ट शुल्क सीमा शुल्क मूल्य का 16% तक सीमित किया जाएगा।

धारा 5

आम प्रावधान

अनुच्छेद 11

विनियम (ईसी) की संख्या 384/96 (1) नं 2026/97 (2), के तहत एंटी डंपिंग या काउंटरवेलिंग उपायों के अधीन जिन उत्पादों पर टैरिफ वरीयताएँ हैं इस विनियमन के लागू होने के बाद लगाया और क्षति सीमा पर आधारित है, जिसमें से कि क्षति सीमा निकाली थी आयात कीमतों से परिलक्षित टैरिफ वरीयताओं को सीमित किया जाएगा।

अनुच्छेद 12

1. एक लाभार्थी देश में उत्पादों के मूल स्थान के संबंध में, निम्नलिखित मानदंडों के या तो: लगातार तीन वर्षों के दौरान, एक क्षेत्र में पूरा किया गया हो, अनुच्छेद 7 और 10 के रूप में संदर्भित टैरिफ वरीयताओं को हटा दिया जाएगा।

(क) - अनुबंध II में परिभाषित देश के विकास सूचकांक, 2, की तुलना में उच्च है और

- अनुबंध I में सूचीबद्ध सभी देशों और क्षेत्रों से उसी उत्पाद समुदाय आयात के 25% से अधिक उस देश ने उपभोग किया है, व्यवस्थाओं में शामिल है और आयात समुदाय सभी देशों और क्षेत्रों के सारे उत्पादों का संबंध है

(ख) संबन्धित क्षेत्र की विशेषज्ञता के सूचकांक सीमा है कि देश के विकास सूचकांक को इसी रूप में अनुबंध II में परिभाषित की तुलना में अधिक है, और

अनुबंध I में सूचीबद्ध किए गए सभी देशों और क्षेत्रों को एक ही उत्पाद के आयात समुदाय का 2% से अधिक. देश ने उपभोग किया है, क्षेत्र के सभी उत्पादों के संबंध में उस देश से आयात समुदाय की व्यवस्था में शामिल है।

2. जहां एक क्षेत्र है, के संबंध में अनुबंध I के कॉलम डी के अनुसार जो टैरिफ वरीयताओं को हटा दिया गया है या इस अनुच्छेद के अनुसार बाद में लिए गए निर्णय को लगातार तीन वर्षों के दौरान, पूरा नहीं किया है, या तो मानदंड पैरा 1 में निर्धारित टैरिफ वरीयताओं को फिर से स्थापित किया जाएगा।

3. प्रत्येक वर्ष के 01 सितंबर को उपलब्ध सबसे नवीनतम आंकड़ों के आधार पर पैराग्राफ 1 और 2 में नीचे निर्धारित शर्तों को पूरा किए गए सेक्टरों को आयोग स्थापित करेगा।

4. सबसे नवीनतम वर्ष के संबंध में है, जिसके लिए डेटा उपलब्ध है, जो पैरा 1 में निर्धारित मानदंड पूरा किया गया है सूचीबद्ध सेक्टरों को आयोग यूरोपीय समुदाय के आधिकारिक जर्नल में एक नोटिस प्रकाशित करेगा।

5. इस विनियमन के लागू हो जाने पर और प्रत्येक वर्ष के अंत से पहले, आयोग अनुच्छेद 38 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, जिन क्षेत्रों में पैरा 1 में निर्धारित शर्त पूरा कर के संबंध में टैरिफ वरीयताओं को दूर करने के लिए और जिन क्षेत्रों पैरा 2 में निर्धारित शर्त पूरा कर के लिए टैरिफ वरीयताओं को फिर से स्थापित करने के लिए निर्णय लेंगे।

6. पहले पैरा 5 के अनुसार लिए गए निर्णय 1 जनवरी 2003 को प्रभाव में आएगा। इसके बाद, पैरा 5 के अनुसार एक वर्ष के दौरान लिए गए निर्णय के बाद दूसरे वर्ष की 1 जनवरी को प्रभाव में आएगा।

7. आयोग पैरा 5 के अनुसार संबंधित लाभार्थी देश को एक निर्णय और तारीख, जिस पर उस निर्णय प्रभावित है, को अधिसूचित करेगा।

